भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2111
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

वन स्टॉप सेंटरों का प्रभावी संचालन

2111. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन संख्या 181 के प्रभावी संचालन के लिए कोई नई कार्य योजना लागू कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में संचालित और निकट भविष्य में खोले जाने के लिए प्रस्तावित ओएससी का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल के घटक हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता एवं सहयोग प्रदान करता है। यह सेंटर जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता एवं मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

अब तक, देश भर में 864 ओएससी कार्यशील हैं। शुरुआत से अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2025 तक, देश में 12.67 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई

है। महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) **चौबीस घंटे चलने वाले यूनिवर्सल टोल-फ्री नंबर 181** के माध्यम से देश भर की महिलाओं और बालिकाओं को निर्बाध आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता और सूचना सेवा प्रदान करती है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। पश्चिम बंगाल सरकार महिला हेल्पलाइन का संचालन नहीं कर रही है। 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2025 तक, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में 93.48 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की जा चुकी है।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। इसके अलावा, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड वर्ष में एक बार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

अब तक, मध्य प्रदेश में अनुमोदित 65 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) में से 57 कार्यशील हैं और विगत तीन वर्षों में इन ओएससी के माध्यम से 65,187 महिलाओं की सहायता की गई है। चूंकि यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी स्थापित करने और उन जिलों में जहां महिलाओं के प्रति अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है तथा आकांक्षी जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

*****